



2026: AHC: 30208-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **93/2026**

सुनील सिंह याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य उत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: रजनीश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव

उत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता: जगदीश पाठक (एस.सी.), विवेक मिश्रा, नागेंद्र नाथ मिश्रा

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका कथित रूप से जनहित में, याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 ('संहिता') की धारा 67 के तहत पारित आदेशों के निष्पादन की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. याचिकाकर्ता ने संहिता की धारा 67 के तहत पारित 56 आदेशों को संलग्न किया है और वर्तमान याचिका दायर करके उनके निष्पादन की मांग की है।
3. इस तथ्य के अलावा कि संहिता की धारा 67 के तहत पारित आदेशों के निष्पादन की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर करना स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका में एक भी प्रभावित व्यक्ति को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल न करने का विकल्प

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चुना है। इसके अलावा, इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है कि क्या संहिता की धारा 67 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ किसी चुनौती के संबंध में कोई जांच की गई है, क्योंकि एक प्रस्तावित आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ता ने संकेत दिया है कि संहिता की धारा 67 के तहत पारित आदेशों को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाएं इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं, जिनमें उक्त आदेशों पर रोक लगा दी गई है।

4. आगे यह आरोप भी लगाए गए हैं कि याचिका मुख्य रूप से उन ग्रामीणों से पैसे वसूलने के उद्देश्य से दायर की गई है जिनके घर/भूमि संहिता की धारा 67 के तहत पारित आदेशों में शामिल हैं।
5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को, पिछली बार, तथ्यों को छिपाने के संबंध में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था; आज, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता याचिका वापस लेने की प्रार्थना करते हैं, जो अनिवार्य रूप से प्रस्तावित आवेदक/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करता है।
6. उचित जांच किए बिना और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर जनहित याचिकाएं दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

11 फरवरी, 2026

ए.एच.ए./ज्योतिषना

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"